पटना उच्च न्यायालय में
आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1386/2017

थाना काण्ड संख्या ४९/२०१६ से उत्पन्न थाना-किशनपुर जिला-सुपौल

मो. नसीम पुत्र स्वर्गीय मो। आलम, निवासी गाँव-पीरगंज, पी. एस.-किशनपुर, जिला-सुपालसुपौल ।

... ..अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

.....प्रतिवादी

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ के लिए : श्री समीर रंजन,
राज्य के अधिवक्ता : श्री सुजीत कुमार सिंह, ए. पी. पी.

अपील – उस निर्णय के विरुद्ध दायर की गई, जिसके तहत निचली अदालत ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया।

निर्णय –

- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिए गए बयान को साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएँ हैं। अदालत अभियुक्त के बयान के कुछ भागों पर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आधार पर भरोसा कर सकती है और उसे दोषी ठहरा सकती है। हालांकि, इस धारा के तहत दिए गए बयान को अलग-थलग नहीं बल्कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, अभियुक्त द्वारा धारा 313 के तहत दिया गया बयान केवल उसी हद तक अदालत द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ तक वह अभियोजन के मामले से मेल खाता है, लेकिन केवल इसी आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। (पैरा 21)
- चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी द्वारा दी गई गवाही का समर्थन करता है। (पैरा 22)
- यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ केवल धारा 313 के तहत अदालत में दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर अपीलकर्ता/अभियुक्त को दोषी ठहराया गया हो। (पैरा 22.1)

अपील खारिज की जाती है। (पैरा 24)

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. श्री अंशुमान

मौखिक न्यायादेश/निर्णय

(निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तिथि - 07-01-2025

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 374(2) के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें किशनपुर थाना कांड संख्या 49/2016 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 149/2016 (जी.आर. संख्या 466/2016) में विद्वान एफ.टी.सी. संख्या 2, सुपौल द्वारा दिनांक 04.09.2017 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 07.09.2017 को पारित सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत संबंधित विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

2. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है -

2.1. सूचक असजादी खातून ने 10.03.2016 को किशनपुर पुलिस स्टेशन के समक्ष लिखित शिकायत दी, जिसमें उसने कहा है कि 09.03.2016 को वह अपने पति मोहम्मद तस्लीफ (मृतक) के साथ थारबिड़ा स्टेशन बाजार से घरेलू सामान खरीदकर पीरगंज स्थित अपने घर आ रही थी। लगभग 3:30 बजे शाम को जब वह कोशी बांध के पश्चिम में पुल के पास पहुंची, तो अचानक आरोपी मोहम्मद नसीम बांस के बगीचे से आया और उसके सामने उसके पति के पेट पर चाकू से वार किया और उसी बांस के बगीचे की ओर भाग गया। उसने आरोप लगाया कि उसका पति सड़क पर गिर गया और मदद के लिए रोने लगा। फिर, उसके गाँव के दो लड़के वहाँ आए और उसके पति को अपनी मोटरसाइकिल पर किशनपुर अस्पताल ले गए जहाँ से उसके पति को सुपौल सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बेहतर इलाज के लिए दरभंगा ले जाते समय एम्बुलेंस में उनके पति की मौत हो गई। उसने आगे कहा है कि उसका पति चार दिन पहले राजस्थान से उसके गाँव आया था। उसने आगे आरोप लगाया है कि, उसके पति को चाकू मारने के बाद, आरोपी उसके मायका (मातृ गृह) गया और उसकी छोटी बहन सरबरी बेगम के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे मारने की भी कोशिश की, लेकिन जब उसने चिल्लाना शुरू किया तो किसी तरह उसकी बहन की जान बच गई।

2.2. प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के बाद, जांच अधिकारी ने जांच शुरू की और जाँच के दौरान, उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए, साक्ष्य एकत्र किए और उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से

सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 209 के तहत संबंधित सत्र न्यायालय को यह कार्य सौंपा, जहां इसे 2016 के सत्र परीक्षण संख्या 149 (जी. आर. संख्या 466/2016) के रूप में दर्ज किया गया था।

2.3. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों से पूछताछ की थी और दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए थे। इसके बाद, अपीलार्थी/अभियुक्त का आगे का बयान संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के समापन के बाद, निचली अदालत ने विवादित निर्णय और दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित किया, जिसके खिलाफ अपीलार्थी/दोषी ने वर्तमान अपील दायर किया है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री समीर रंजन और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान ए.पी.पी. श्री सुजीत कुमार सिंह को सुना गया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्यतः यह तर्क दिया कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने पी.डब्ल्यू.-7 (सूचना देने वाला) को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश किया है, जबकि पी.डब्ल्यू.-1 से पी.डब्ल्यू.-5 तक सुनी-सुनाई बातों पर आधारित गवाह हैं। आगे यह भी कहा गया कि विचरण न्यायालय ने सूचना देने वाले (पी.डब्ल्यू.-7) तथा जांच अधिकारी (पी.डब्ल्यू.-8) से जिरह करने का उचित अवसर नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के प्रति पक्षपात हुआ। आगे यह भी कहा गया कि विचरण न्यायालय ने केवल अपीलकर्ता द्वारा धारा 313 के तहत अपना आगे का बयान देते समय किए गए इकबालिया बयान पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है। इसलिए केवल अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा धारा 313 के तहत दिए गए बयान पर भरोसा करते हुए उसे दोषी ठहराया गया है, जो कानून की नजर में उचित नहीं है। इसलिए, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए और वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाए। अभिलेख से यह भी पता चला है कि अपीलकर्ता मार्च, 2016 से हिरासत में है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:-

(i) **महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह और अन्य, (1992) 3 एससीसी 700** में रिपोर्ट किया गया।

(ii) **मोहन सिंह बनाम प्रेम सिंह और अन्य, (2002) 10 एससीसी 236** में रिपोर्ट किया गया।

(iii) **धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2010) 7 एससीसी 759** में रिपोर्ट किया गया।

(iv) **अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य, (2010) 12 एससीसी 350** में रिपोर्ट किया गया।

6. दूसरी ओर, विद्वान ए.पी.पी. ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। विद्वान ए. पी. पी. मुख्य रूप से प्रस्तुत किया कि सूचना देने वाली स्वयं प्रश्रगत घटना की चश्मदीद गवाह है और उसने अभियोजन

पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है। यहां तक कि पीडब्लू-6, डॉक्टर जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था, ने भी चश्मदीद गवाह के बयान का समर्थन किया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि पीडब्लू-2, जो सूचना देने वाले की बहन है, ने भी फरदबयान में उल्लिखित दूसरी घटना का समर्थन किया है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। इस स्तर पर, विद्वान ए. पी. पी. ने संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपीलार्थी/अभियुक्त के बयान का भी उल्लेख किया है जिसमें अपीलार्थी ने विशेष रूप से स्वीकार किया “हाँ मैंने मार दिया, बहुत दिन से झंझट चलता था इसलिए मार दिया”

7. अतः विद्वान ए. पी. पी. प्रस्तुत करते हैं कि संहिता की धारा 313 के तहत स्वयं अपीलार्थी द्वारा दिया गया संस्करण अभियोजन पक्ष और विशेष रूप से पीडब्लू-7 (चश्मदीद गवाह) के मामले की पुष्टि करता है। अतः विद्वान ए. पी. पी. ने आग्रह किया कि विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटियां नहीं की गई हैं। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाए।

8. हमने विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और विचरण न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत के समक्ष 8 गवाहों से पूछताछ की थी। यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-1 से पीडब्लू-5 ने विशेष रूप से न्यायालय के समक्ष बयान दिया है कि वे अपीलार्थी द्वारा मृतक को झटका देने की घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से पीडब्लू-7 असजादी खातून (सूचक) द्वारा दिए गए बयान पर आधारित है। सूचना देने वाला मृतक की पत्नी है। उसने विशेष रूप से अपने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि उसने मामला दायर किया था। यह घटना 9 मार्च, 2016 को लगभग 3 बजे हुई जब वह अपने पति और दो बच्चों के साथ वर्सिटा बाजार गई थी। लौटते समय, लगभग 3:30 बजे शाम को वह कोशी बांध के पुल के पश्चिम में पहुंची। वह अपने दो बच्चों के साथ अपने पति से चार कदम आगे चल रही थी। जब उसका पति चिल्लाया, तो उसने मुड़कर देखा कि आरोपी मोहम्मद नसीम उसके पति के पेट से चाकू निकाल रहा था। जब वह चिल्लाते हुए अपने पति के पास पहुंची तो आरोपी बांस के बगीचे के अंदर भाग गया। उसका चिल्लाना सुनकर ग्राम का एक लड़का रहमत आया और उसके पति को किशनपुर अस्पताल ले गया। वहां से उसके पति को सुपौल अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुपौल के डॉक्टर ने उसे दरभंगा अस्पताल ले जाने के लिए कहा। वह अपने पति को एम्बुलेंस में ले गई और जब वे सुपौल और किशनपुर के बीच पहुँचे, तो उनके पति की मृत्यु हो गई। उसने आगे कहा है कि आरोपी उसका देवर है। उसने कहा है कि उसका पति राजस्थान में रहता था। उसके पति को घर आते हुए केवल दस दिन हुए थे जब आरोपी ने उसे चाकू मार दिया। उसने अदालत में मौजूद आरोपी की पहचान की। उसने आगे कहा है कि उसने पुलिस स्टेशन में

मामला दर्ज कराया था। उन्होंने सुनने और समझने के बाद हस्ताक्षर किए। वह अपने हस्ताक्षर की पहचान करती है।

8.1. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना उचित है कि बचाव पक्ष की ओर से कोई भी सूचना देने वाले (पीडब्लू-7) से जिरह करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ।

9. उपरोक्त गवाह, अर्थात् पी.डब्लू.-7 द्वारा दिए गए बयान से यह स्पष्ट है कि उसने लिखित शिकायत में दिए गए अपने बयान का समर्थन किया था। हालाँकि, लिखित शिकायत और सूचक की जाँच में मामूली विसंगति है। मुख्य परीक्षा के पैरा-2 में, पीडब्लू-7 (चश्मदीद गवाह) ने विशेष रूप से बयान दिया है कि अपीलार्थी चाकू के साथ मौजूद था और वह उसके पति के पेट से चाकू निकाल रहा था और उसके बाद आरोपी घटना स्थल से भाग गया। उन्होंने यह भी कहा है कि घायल को शुरू में किशनपुर अस्पताल और उसके बाद सुपौल अस्पताल ले जाया गया जहाँ से घायल को दरभंगा अस्पताल रेफर कर दिया गया और और जब घायल को एम्बुलेंस से दरभंगा ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उक्त गवाह ने अदालत में आरोपी की पहचान भी की है। इस स्तर पर पीडब्लू-6 (डॉ. महेंद्र चौधरी) द्वारा दिए गए बयान की भी बारीकी से जांच की जानी चाहिए। पीडब्लू-6 ने विशेष रूप से निम्नानुसार पदच्युत किया है:

“बाहरी निष्कर्ष (दिखने पर)

गोरा रंग, दोनों आँखें बंद, मुँह बंद और चारों अंगों पर कठोर मृत्यु।

(1) ऊर्ध्वाधर तेज काटने वाले छुरा घोंपने से ऊपरी पेट के दाहिने तरफ 1 1/2 "और 1" पेट तक गहरा घाव होता है, जो बाहरी और आंतरिक रक्तस्राव रक्तस्राव और सदमे के कारण सी. आर. विफलता के कारण होता है।

मृत्यु के बाद से 24 घंटे बीत गए। यह पीएम रिपोर्ट मेरे कलम और हस्ताक्षर में है जिस पर एक्स. टी.-1 अंकित है।

अत्यधिक रक्तस्राव के कारण भी मृत्यु "

10. इस प्रकार, मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान से यह पता चलता है कि मेडिकल साक्ष्य पीडब्लू-7 (चश्मदीद गवाह) द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करते हैं।

11. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि सूचक द्वारा दी गई लिखित शिकायत में, उसने विशेष रूप से कहा था कि सूचक के पति के पेट पर वार करने के बाद, अपीलार्थी/आरोपी उक्त स्थान से भाग गया और उसके बाद वह उसके मायके पीरगंज गया और सूचक की बहन के साथ भी दुर्व्यवहार किया। हालाँकि, जब उसकी बहन ने शोर मचाया तो आरोपी वहाँ से भी भाग गया। अभिलेख से पता चलता है कि सूचक की बहन सरबरी बेगम से अभियोजन पक्ष द्वारा पीडब्लू-2 के रूप में पूछताछ की गई है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा-1 में विशेष रूप से यह बयान दिया है कि घटना के दिन

दोपहर 03:00 बजे वह अपने घर पर थी। आरोपी उसके आंगन में आया और उसका नाम पुकारा। वह घर से बाहर आ गई। फिर वह चाकू लेकर आंगन में घुस गया। जब उसने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने शोर मचा दिया। ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर आरोपी भाग गया। उसके बाद उसे पता चला कि आरोपी ने उसके जीजा को चाकू मार दिया है।

11.1. बचाव पक्ष द्वारा उक्त गवाह से जिरह की गई।

12. अतः हमारा विचार है कि दूसरा पीडब्लू-7 द्वारा दी गई लिखित शिकायत में उल्लिखित घटना भी पीडब्लू-2 द्वारा समर्थित है।

13. इस स्तर पर, हम पीडब्लू-8 गोंदा राम सोई (जांच अधिकारी) द्वारा दिए गए बयान की भी जांच करना चाहेंगे, जिन्होंने जांच की थी। पीडब्लू-8 द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, सूचना मिलने के बाद, वह घटनास्थल पर पहुंचे और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद, सूचक द्वारा दी गई लिखित शिकायत प्राप्त हुई और उसने गवाहों के बयान, घटना स्थल की जांच की और जांच के दौरान सबूत एकत्र किए। इस बीच, उक्त गवाह ने 13.05.2016 पर अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया। वास्तव में, अपीलार्थी ने उक्त पुलिस अधिकारी के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। यहाँ भी, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि बचाव पक्ष ने उक्त गवाह से जिरह नहीं की।

14. विचरण न्यायालय के रिकॉर्ड से, यह सामने आएगा कि चूंकि बचाव पक्ष का वकील न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था, इसलिए विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को उसके मामले का बचाव करने के अनुरोध पर बचाव पैनल के अधिवक्ता की सेवाएं प्रदान कीं और उसके बाद, 28.08.2017 पर, संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थी/अभियुक्त का आगे का बयान दर्ज किया गया। इस स्तर पर, उक्त कथन का उल्लेख करना प्रासंगिक है जो नीचे दिया गया है:

“प्रश्न:- क्या आपने गवाहों का गवाही सुना है ?

उत्तर :- जी हाँ ।

प्रश्न:- आपके विरुद्ध आरोप है की आपने मुदया के पति मो. तसरीफ के पेट में चाकू मार दिया जिसके कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गया । आपको क्या कहना है ?

उत्तर :- हाँ मैंने मार दिया, बहुत दिन से झंझट चलता था इसलिए मार दिया ।

प्रश्न:- सफाई में क्या कहना है ?

उत्तर :- कुछ नहीं कहना है ।”

15. इस प्रकार, अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा धारा 313 के तहत दिए गए उपरोक्त बयान से पता चलता है कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत के समक्ष कबूल किया है कि उसने किसी झगड़े के कारण मृतक की हत्या की थी।

16. हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा हमने संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी द्वारा दिए गए बयान को भी देखा है। अब, यह अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क है कि विचारण न्यायालय ने केवल अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष किए गए स्वीकारोक्ति पर भरोसा करते हुए गलती की है क्योंकि दोषसिद्धि केवल उसी आधार पर नहीं की जा सकती है।

17. इस स्तर पर, हम महाराष्ट्र राज्य (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-51 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

“51. इससे यह सवाल उठता है कि क्या धारा 313 के तहत दर्ज किया गया ऐसा बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है। चूंकि अभियुक्त को कोई शपथ नहीं दलाई जाती है, इसलिए अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान सख्त तौर पर साक्ष्य नहीं माने जाएंगे। यही कारण है कि उप-धारा (3) में कहा गया है कि यदि अभियुक्त गलत उत्तर देता है तो वह स्वयं को दंडनीय नहीं ठहराएगा। इसके बाद उप-धारा (4) आती है जिसमें कहा गया है:

“313. (4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को ऐसी जांच या मुकदमे में ध्यान में रखा जा सकता है, और किसी अन्य अपराध की जांच या मुकदमे में उसके पक्ष या उसके खिलाफ साक्ष्य दिया जा सकता है, जो इस तरह के उत्तरों से पता चलता है कि उसने किया है।

इस प्रकार धारा 313 के तहत अपनी जांच के जवाब में आरोपी द्वारा दिए गए उत्तरों को ऐसी जांच या मुकदमे में ध्यान में रखा जा सकता है। उपरोक्त उप-धारा के सरल पठन पर यह बहुत कुछ स्पष्ट है। इसलिए, हालांकि कड़ाई से साक्ष्य नहीं है, उप-धारा (4) अनुमति देती है कि इसे उक्त जांच या मुकदमे में विचार में लिया जा सकता है। महाराष्ट्र राज्य बनाम आर. बी. चौधरी [(1967) 3 एस. सी. आर. 708:ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 110:1968 क्री एलजे 95]। यह न्यायालय हेट सिंह भगत सिंह बनाम एम. बी. राज्य के मामले में [1951 एस. सी. सी. 1060:1953 क्रि एल. जे. 1933:ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 468] ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 313 की परीक्षा के तहत एक अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तर का उपयोग अपने अपराध को साबित करने के लिए किया जा सकता है जितना कि अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य का। नारायण सिंह बनाम पंजाब राज्य (1963) 3 एस. सी. आर. 678:(1964) 1 सी. आर. आई. एल. जे. 730] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि अभियुक्त उस अपराध को स्वीकार करता है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है तो न्यायालय उस स्वीकारोक्ति पर भरोसा करते हुए उसे दोषी ठहराने के लिए आगे बढ़ सकता है। उस सटीक भाषा को बताने के लिए जिसमें तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने प्रश्न का उत्तर दिया, पृष्ठ 684-685 पर प्रासंगिक टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करना फायदेमंद होगा:

“प्रथम उप-धारा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत, जहां तक यह सामग्री है, न्यायालय जांच या मुकदमे के किसी भी स्तर पर और अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच के बाद और आरोपी को उसके बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले आरोपी व्यक्ति से सवाल कर सकता है ताकि वह उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या कर सके। धारा 342 के तहत जांच मुख्य रूप से उन मामलों के लिए निर्देशित की जानी है जिन पर अभियोजन पक्ष को आरोपी से उसके बयान या घटना के स्पष्टीकरण—यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए साक्ष्य दिया गया है जो आरोप और उसके बचाव का विषय है। उप-धारा (3) द्वारा अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को जाँच या विचारण में 'विचार में लिया जा सकता है।' यदि अभियुक्त व्यक्ति धारा 342 के तहत अपनी परीक्षा में अपने विरुद्ध आरोपित अपराध को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय उस स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे दोषी ठहरा सकता है, लेकिन यदि वह स्वीकार नहीं करता है और अपने खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को समझाते हुए अपना पक्ष स्थापित करता है और यह अनुरोध करते हुए अपने आचरण की व्याख्या करना चाहता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, तो अभियुक्त के बयान पर केवल संपूर्णता में ही विचार किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

धारा 313 की उप-धारा (1) पुरानी संहिता की धारा 342 की उप-धारा (1) के अनुरूप है, सिवाय इसके कि अब इसे दो भागों में विभाजित किया गया है और इसमें यह स्पष्ट करने के लिए प्रावधान जोड़ा गया है कि समन मामलों में जहां खंड (बी) के तहत आरोपी की उपस्थिति को उसकी परीक्षा के साथ समाप्त किया जाता है, उसे भी समाप्त किया जा सकता है। धारा 313 की उप-धारा (2) पुरानी उप-धारा (4) को पुनः प्रस्तुत करती है और वर्तमान उप-धारा (3) जूरी प्रणाली के उन्मूलन के कारण आवश्यक परिवर्तन को छोड़कर पुरानी उप-धारा (2) से मेल खाती है। वर्तमान उप-धारा (4), जिससे हमें सरोकार है, पुरानी उप-धारा (3) का शाब्दिक पुनरुत्पादन है। इसलिए, वनाच्छादित अवलोकन समान बल के साथ लागू होते हैं”

18. मोहन सिंह (ऊपर) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा-27 और 30 में

निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“27. धारा 313 सी. आर. पी. सी. के तहत आरोपी द्वारा बचाव में दिए गए बयान को निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य को विश्वास दिलाने के लिए सहायता ली जा सकती है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत इस तरह के बयान के केवल एक हिस्से को ही उसकी दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है। इस विषय पर कानून लगभग तय कर चुका है कि आरोपी के सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान पर या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से भरोसा किया जा सकता है। यदि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर दोषमुक्ति भाग गलत पाया जाता है तो उसके बयान के आक्षेपात्मक भाग पर भरोसा करना भी संभव हो सकता है। निशी कांत झा बनाम बिहार राज्य देखें [(1969) 1 एस. सी. सी. 347:ए. आई. आर 1969 एस. सी. 422]:(एस. सी. पी. 357-58, पैरा 23)

“23. इस मामले में प्रदर्शनी 6 में बयान का निर्दोषकारी हिस्सा न केवल स्वाभाविक रूप से असंभव है, बल्कि अन्य सबूतों से विरोधाभासी भी है। इस कथन के अनुसार, अपीलार्थी को जो चोट लगी, वह पीड़ित पर हमले को रोकने के लिए अपीलार्थी द्वारा लाल मोहन शर्मा का हाथ पकड़ने के प्रयास के कारण हुई थी। सी. आर. पी.

सी. की धारा 342 के तहत स्वयं आरोपी के बयान से इसका खंडन किया गया था कि उसे एक चरवाहे के साथ हाथापाई में चोट लगी थी। उनके शरीर पर पाई गई चोट जब डॉक्टर द्वारा 13-10-1961 पर उनकी जांच की गई तो ये दोनों संस्करण नकारात्मक हो गए। इन संस्करणों में से कोई भी अत्यधिक रक्तस्राव के लिए जिम्मेदार नहीं है जिसके कारण उन्होंने अपने कपड़े धोए और पात्रो नदी में स्नान किया, रक्तस्राव की मात्रा और रक्त के धब्बों को धोना इतना महत्वपूर्ण था कि राम किशोर पांडे, पीडब्लू 17 का ध्यान आकर्षित किया और उनसे इसका कारण पूछा। खून बहना कोई साधारण बात नहीं थी क्योंकि उसके कपड़े खून से सना हुआ था और साथ ही उसकी किताबें, उसकी व्यायाम की किताब और उसकी बेल्ट और जूते भी। रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उसके व्यक्ति पर जो चाकू मिला था, वह खून से सना हुआ था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार यह चाकू पीड़ित पर चोटों का कारण हो सकता है। इस तरह की परिस्थितियों में, प्रदर्शनी 6 में अपीलार्थी के बयान के दोषमुक्ति भाग को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त सबूत होने के कारण, उच्च न्यायालय ने दोषी पक्ष को स्वीकार करके तथा अन्य साक्ष्यों के साथ उसका मिलान करके सही काम किया है, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलकर्ता ही अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है।”

30. सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है। इसका उपयोग अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, यह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का विकल्प नहीं है। जैसा कि निशिकांत [(1969) 1 एस. सी. सी. 347 के मामले में कहा गया है: ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 422] इस न्यायालय द्वारा, यदि उनके बयान का दोषमुक्ति भाग झूठा पाया जाता है और अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य विश्वसनीय है, तो उनके बयान के दोषारोपण भाग को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को आश्वासन देने के लिए सहायता ली जा सकती है। यदि अभियोजन पक्ष का साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, तो उसके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान को उसकी दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है।”

19. धरणीधर (ऊपर) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा-28 से पैरा-32 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“28. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी द्वारा दिए गए बयान का उपयोग अदालत द्वारा इस हद तक किया जा सकता है कि यह अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप है। किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए यही एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में, अदालत के समक्ष आरोपी का बयान, कुछ हद तक, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप है और उस हद तक, अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि की जा सकती है और अदालत द्वारा इसे सही माना जा सकता है। इस धारा के पीछे विधायी इरादे के दोहरे उद्देश्य प्रतीत होते हैं। सबसे पहले, अभियुक्त को उसके खिलाफ पेश होने वाली परिस्थितियों को समझाने का अवसर प्रदान करना। दूसरा, न्यायालय को अभियुक्त से पूछताछ करने और उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर मिले, जो किसी शर्मनाक स्वीकारोक्ति या बयान के लिए फंसने के डर से मुक्त हो सकता है।

29. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करते समय न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली उचित कार्यप्रणाली अभियुक्त का ध्यान उस अपराध के संबंध में परिस्थितियों और पर्याप्त साक्ष्य

की ओर आकर्षित करना है, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है और उसका स्पष्टीकरण आमंत्रित करना है। दूसरे शब्दों में, यह एक अभियुक्त को अदालत के समक्ष यह बताने का अवसर प्रदान करता है कि कानून के अनुसार सच्चाई क्या है और उसका बचाव क्या है। यह अभियुक्त पर था कि वह उस अवसर का लाभ उठाए और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो यह अदालत पर है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान के संदर्भ में अपने साक्ष्य पर अभियोजन पक्ष के मामले की जांच करे।

30. हेट सिंह भगत सिंह बनाम मध्य भारत राज्य [1951 एस. सी. सी. 1060:ए. आई. आर. 1953 एससी 468:1953 सी. आर. आई. एल. जे. 1933] ने वर्तमान सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के समतुल्य पुरानी सी. आर. पी. सी. की धारा 342 पर विचार करते हुए कहा कि दिए गए अभियुक्त के उत्तर का उपयोग अन्य पूछताछों या अन्य अपराधों के लिए परीक्षणों में किया जा सकता है।

31. नारायण सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1964) 1 क्राई एल. जे. 730:(1963) 3 एस. सी. आर. 678] इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (सीआरआई एलजे पी. 733, पैरा 4)

“4. ... प्रथम उप-धारा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत, जहां तक यह सामग्री है, अदालत जांच या मुकदमे के किसी भी स्तर पर और अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच के बाद और आरोपी को उसके बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले आरोपी व्यक्ति से सवाल कर सकती है ताकि वह उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या कर सके। धारा 342 के तहत जांच मुख्य रूप से उन मामलों के लिए निर्देशित की जानी है जिन पर अभियोजन पक्ष के लिए सबूत पेश किए गए हैं, ताकि आरोपी से उस घटना के उसके बयान या स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, का पता लगाया जा सके जो आरोप और उसके बचाव का विषय है। उप-धारा (3) द्वारा अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को जाँच या विचारण में 'विचार में लिया जा सकता है। यदि अभियुक्त व्यक्ति धारा 342 के तहत अपनी जाँच में अपने खिलाफ आरोपित अपराध को स्वीकार करता है, तो अदालत उस स्वीकारोक्ति पर भरोसा करते हुए उसे दोषी ठहराने के लिए आगे बढ़ सकती है, लेकिन यदि वह स्वीकार नहीं करता है और अपने खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को समझाते हुए अपना पक्ष स्थापित करता है और यह दलील देते हुए अपने आचरण की व्याख्या करना चाहता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, तो अभियुक्त के बयान को केवल पूरी तरह से ध्यान में रखा जा सकता है।”

32. नारायण सिंह मामले [(1964) 1 सी. आर. आई. एल. जे. 730 में निर्धारित कानून के अनुसार [(1963) 3 एस. सी. आर. 678] महाराष्ट्र राज्य में सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुखदेव सिंह [(1992) 3 एस. सी. सी. 700:1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 705:1992 सी. आर. आई. एल.

जे. 3454] ने आगे इस सवाल पर चर्चा की कि क्या सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है और यह निष्कर्ष दर्ज किया कि 1973 की धारा 313 सी. आर. पी. सी. के तहत अपनी जांच के जवाब में आरोपी द्वारा दिए गए उत्तरों को ऐसी जांच या मुकदमे में ध्यान में रखा जा सकता है, हालांकि ऐसा बयान सख्ती से सबूत नहीं है और पैरा 52 में इस प्रकार देखा गया है: (सुखदेव सिंह मामला [(1992) 3 एस. सी. सी. 700:1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 705:1992 क्री एलजे 3454], एससीसी पी।1744)

“52. यहां तक कि पहले सिद्धांत पर भी हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि अदालत मुकदमे के दौरान या संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए उसके बयान में आरोपी द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति या स्वीकारोक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकी।

इस प्रकार यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित है कि मुकदमे के दौरान दर्ज की गई धारा 313 सी. आर. पी. सी. के तहत बयान में आरोपी के प्रवेश या स्वीकारोक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है और अदालत उसे दोषी ठहराने के लिए आगे बढ़ने के लिए इन स्वीकारोक्ति पर भरोसा कर सकती है”

20. अशोक कुमार (ऊपर) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा-29 और पैरा-32 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“29. अब हम वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उठाए गए मुद्दों को एक संकीर्ण दायरे में लाने के लिए हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिए गए आरोपी के बयान का उल्लेख कर सकते हैं। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि दोहरे उद्देश्य को तब प्राप्त करने की कोशिश की जाती है जब अदालतें इस प्रावधान के तहत किसी आरोपी का बयान दर्ज करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन करती हैं। सबसे पहले, अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के खिलाफ उपयोग किए जाने वाले साक्ष्य के प्रत्येक भौतिक टुकड़े को उसके सामने स्पष्ट शब्दों में रखा जाना चाहिए और दूसरा, अभियुक्त को उस साक्ष्य के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने का उचित मौका मिलना चाहिए और साथ ही अपराध में कथित संलिप्तता के संबंध में अपने स्वयं के बयान देने चाहिए। यह दोहरा उद्देश्य आपराधिक न्याय के उचित प्रशासन के हित में और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत बयान का उपयोग अदालत द्वारा किया जा सकता है क्योंकि यह अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करता है। बेशक, प्रति दोषसिद्धि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान पर आधारित नहीं हो सकती है।

32. अभियुक्त के बयान का उपयोग अभियुक्त द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति के उत्तेजक भाग, यदि कोई हो, की सत्यता का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। इसे किसी भी जांच या परीक्षण में ध्यान में रखा जा सकता है लेकिन फिर भी यह मामले में सख्ती से सबूत नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (4) के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को ऐसी जांच या मुकदमे में ध्यान में रखा जा सकता है और किसी अन्य अपराध के लिए किसी अन्य जांच या मुकदमे में अभियुक्त के पक्ष या उसके खिलाफ सबूत के रूप में रखा जा सकता है, जिसके लिए ऐसे उत्तरों से यह पता चलता है कि

उसने अपराध किया है। दूसरे शब्दों में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत एक बयान का सबूत के रूप में उपयोग संहिता के प्रावधानों के अनुसार अनुमत है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएँ हैं। अदालतें अभियुक्त के बयान के एक हिस्से पर भरोसा कर सकती हैं और अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में उसके खिलाफ अन्य साक्ष्यों पर विचार करते हुए उसे दोषी ठहरा सकती हैं, हालाँकि, इस धारा के तहत दिए गए ऐसे बयानों पर अलग से नहीं बल्कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संयोजन में विचार किया जाना चाहिए।”

21. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों से यह कहा जा सकता है कि संहिता की धारा 313 के तहत एक बयान का साक्ष्य के रूप में उपयोग संहिता के प्रावधानों के अनुसार अनुमत है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएँ हैं। अदालतें अभियुक्त के बयान के एक हिस्से पर भरोसा कर सकती हैं और अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में उसके खिलाफ अन्य सबूतों पर विचार करते हुए उसे दोषी ठहरा सकती हैं। हालाँकि, इस धारा के तहत दिए गए बयान पर अलग से नहीं बल्कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संयोजन में विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी द्वारा दिए गए बयान का उपयोग अदालत द्वारा इस हद तक किया जा सकता है कि यह अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप है और यह किसी आरोपी को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, साथ ही धारा 313 के तहत दर्ज अपीलकर्ता के बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जाए, तो यह पता चलेगा कि पीडब्लू-7, जो कि प्रश्रगत घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, ने अपीलकर्ता द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में विशेष रूप से बताया है। सूचक द्वारा दी गई लिखित शिकायत में, अपीलार्थी के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं। पीडब्लू-7 (सूचक) से बचाव पक्ष द्वारा जिरह नहीं की गई है। इसके अलावा, सूचना देने वाले, यानी पीडब्लू-7 द्वारा दिए गए संस्करण की पुष्टि पीडब्लू-6 (डॉक्टर) द्वारा दिए गए बयान से होती है, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था। इस प्रकार, हमारा विचार है कि चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी द्वारा दिए गए संस्करण का समर्थन करते हैं। यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि लिखित शिकायत में सूचना देने वाले द्वारा दो अलग-अलग घटनाओं का वर्णन किया गया है। पहली घटना सूचक के पति के पेट पर चाकू से वार करने के संबंध में है और दूसरी घटना दूसरे स्थान पर सूचक की बहन के साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में है। इस प्रकार, जहाँ तक लिखित शिकायत में वर्णित दूसरी घटना का संबंध है, पीडब्लू-2 ने भी अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया है।

22.1. अब, उपरोक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यदि अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा धारा 313 के तहत दिए गए बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, तो यह पता चलता है कि उसने अदालत के समक्ष बयान देते समय कबूल किया है कि उसने किसी झगड़े के कारण मृतक की हत्या की है। अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान देते समय स्वीकारोक्ति का वह हिस्सा

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप है। इस प्रकार, वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलार्थी/अभियुक्त को संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान देते समय केवल अदालत के समक्ष अपने कबूलनामे पर भरोसा करते हुए दोषी ठहराया गया हो।

23. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारा मानना है कि विचरण न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित करते समय कोई गलती नहीं की है। इसलिए, वर्तमान अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

24. तदनुसार, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(डॉ. अंशुमन, न्यायमूर्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्रेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।